उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 4 | अंक 23 | 1-15 दिसंबर 2021 | ₹ 20/-

सऊदी अरब में तब्लीगी जमात पर प्रतिबंध

- बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की जेएनयू में मांग
- क़ुरान के कथित अपमान के आरोप में श्रीलंकाई को जीवित जलाया
- इजरायली फौज को ईरान पर हमले की तैयारी का आदेश
- पैगम्बर इस्लाम का चित्र बनाने वाले के खिलाफ मुकदमा

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

सऊदी सरकार द्वारा तब्लीगी जमात पर प्रतिबंध से भारतीय मुसलमान नाराज 04
बाबरी मस्जिद पुनर्निर्माण की जेएनयू में मांग 07
इस्लाम के प्रचार के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान 09
मथुरा की ईदगाह का मामला उठाने की तैयारी 10
इस्लाम छोड़कर सनातन की शरण में 12

विश्व

कुरान के कथित अपमान के आरोप में श्रीलंकाई को जीवित जलाया 14
म्यांमार की अपदस्थ प्रधानमंत्री को चार वर्ष की सजा 15
यूक्रेन पर हमला किया तो रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी 16
पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति डांवाडोल 18
मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में 12 वर्ष की सजा 19

पश्चिम एशिया

सऊदी अरब में तब्लीगी जमात पर प्रतिबंध 20
इजरायली फौज को ईरान पर हमले की तैयारी का आदेश 24
संयुक्त अरब अमीरात का फ्रांस से राफेल विमान खरीदने का समझौता 25
सैफ-अल इस्लाम गद्दाफी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति 26
तुर्की द्वारा इजरायल से संबंध स्थापित करने की तैयारी 26

अन्य

मलेशिया में विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे भवन का निर्माण 27
पैगम्बर इस्लाम का चित्र बनाने वाले के खिलाफ मुकदमा 27
बिहार की शिक्षा नीति की आलेचना 28
महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज 28
40 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार 29

सारांश

सऊदी अरब सरकार ने सुन्नी मुसलमानों के विश्वव्यापी संगठन तब्लीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। सऊदी अरब के इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने सभी मस्जिदों के इमामों को यह निर्देश दिया है कि वे अपने जुमा के खुतबे में मुसलमानों को इस संगठन की खतरनाक गतिविधियों से अवगत कराएं और उन्हें इस बात का निर्देश दें कि कोई भी मुसलमान इस संगठन से किसी तरह का संबंध न रखे, क्योंकि यह संगठन समाज का दुश्मन है और यह आतंकवाद का दरवाजा है। एक सप्ताह तक भारत के मुसलमान नेता और मुस्लिम समाचारपत्र इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रहे। यहां तक कि किसी मुस्लिम समाचारपत्र ने इस संबंध में समाचार प्रकाशित करने की जरूरत भी नहीं समझी। मगर जब देश की अन्य भाषाओं के मीडिया में इस संदर्भ में समाचार प्रकाशित होने शुरू हुए तो भारत के मुस्लिम नेता और उनके समाचारपत्र कुंभकर्णी नींद से जागे और उन्होंने सऊदी अरब के इस फैसले की निंदा करनी शुरू कर दी। सबसे विचित्र बात तो यह है कि सऊदी अरब सरकार इस संगठन को आतंकवादी और समाज के लिए खतरा करार दे रही है मगर भारतीय मुस्लिम नेताओं और समाचारपत्रों की नजर में इस संगठन का आतंकवाद से किसी भी तरह का संबंध नहीं है। उनकी नजर में यह विशुद्ध रूप से इस्लामिक संगठन है जो मुसलमानों के उत्थान और कल्याण के कार्यक्रमों में लगा हुआ है। मुस्लिम नेताओं ने यह मांग की है कि सऊदी सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे और तब्लीगी जमात पर लगाए गए प्रतिबंध को तत्काल हटाने की घोषणा करे।

दारूल उलूम देवबंद ने पहली बार तब्लीगी जमात के साथ अपने गहरे रिश्तों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है। दारूल उलूम देवबंद के मोहतमिम (कुलपति) मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कहा है कि तब्लीगी जमात का समर्थन और रक्षा करना उनका धार्मिक कर्तव्य है। इसलिए वे इस जमात पर प्रतिबंध लगाने का विरोध करते रहेंगे। तब्लीगी जमात की स्थापना 1926 में दिल्ली में हुई थी। इस संगठन के सदस्यों की संख्या 40 कराड़ से अधिक बताई जाती है जो विश्व के 150 से भी अधिक देशों में फैले हुए हैं।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें बाबरी मस्जिद को उसी स्थान पर बनाने की मांग की गई। गौरतलब है कि 6 दिसंबर को मुस्लिम संगठन बाबरी मस्जिद शहादत दिवस मनाते हैं। इस अवसर पर अशांति की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन ने किसी भी तरह का कार्यक्रम आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मथुरा में कुछ हिंदू संगठनों ने औरंगजेब द्वारा बनाई गई शाही ईदगाह में भगवान कृष्ण की मूर्ति की स्थापना और जलाभिषेक करने की जो योजना बनाई थी वह प्रशासन के सख्त रूख के कारण विफल हो गई।

पाकिस्तान में रसूल और कुरान के कथित अपमान को लेकर जो जनभावना कट्टरपंथियों द्वारा भड़काई जा रही है उसका शिकार श्रीलंका का एक नागरिक हुआ है। बताया जाता है कि 49 वर्षीय प्रियंथा कुमारा सियालकोट में एक कपड़ा फैक्ट्री में महाप्रबंधक के रूप में कार्य कर रह थ। फैक्ट्री परिसर में पाकिस्तान के एक संगठन ने कुछ पोस्टर लगाए थे, जिन पर कथित रूप से कुरान की आयतें लिखी हुई थीं। श्रीलंका के इस नागरिक ने इन पोस्टरों को वहां से उतार दिया। इस घटना को कट्टरपंथियों ने खूब नमक मिर्च लगाकर प्रसारित किया जिसके नतीजे के तौर पर हजारों लोगों की उग्र भीड़ ने फैक्ट्री पर हमला करके श्रीलंका के इस नागरिक को पीट-पीटकर जिंदा जला दिया।

सऊदी सरकार द्वारा तब्लीगी जमात पर प्रतिबंध से भारतीय मुसलमान नाराज

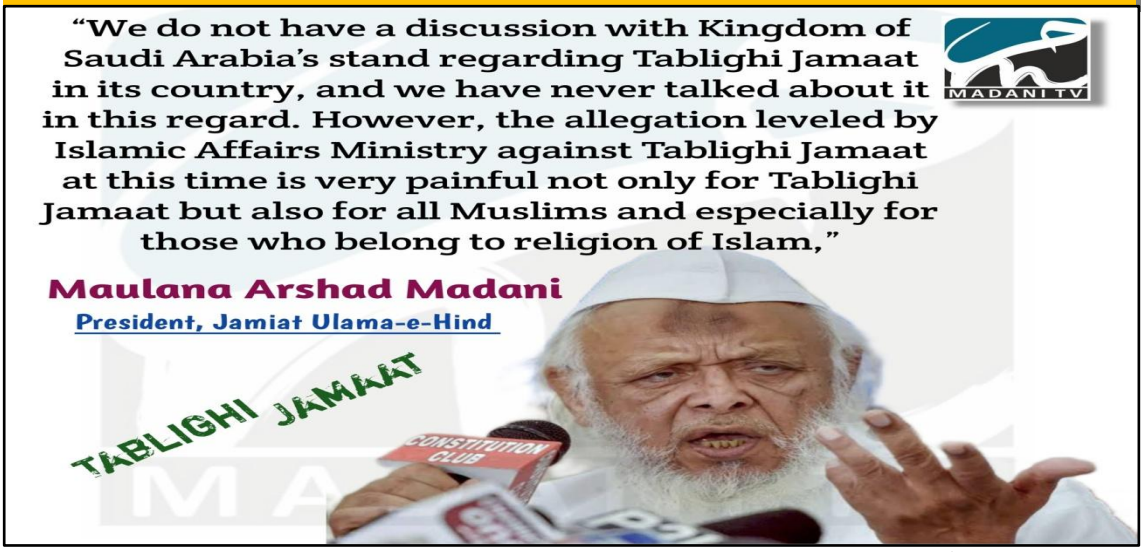

इंकलाब (15 दिसंबर) के अनुसार जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सऊदी अरब के भारत स्थित राजदूत डॉ. सऊद मोहम्मद अल-साती से मुलाकात करके सऊदी अरब द्वारा तब्लीगी जमात पर लगाए गए प्रतिबंध पर विरोध प्रकट किया है और कहा है कि इस प्रतिबंध से हमारे देश में मुसलमानों और मदरसों के लिए दुश्वारियों में वृद्धि हो जाएगी। उन्होंने कहा कि तब्लीगी जमात पर जो आरोप सऊदी सरकार ने लगाए हैं वह सरासर गलत हैं, क्योंकि इस संगठन का राजनीति या सरकार से कोई वास्ता नहीं रहा है और यह संगठन अमन और सद्भावना का संदेश शुरू से ही देता आ रहा है। मौलाना ने सऊदी सरकार के इस्लामिक मामलों के मंत्रालय को एक ज्ञापन देकर इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और इस्लाम के हित के खिलाफ बताया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि तब्लीगी जमात का संबंध क्योंकि दारूल उलूम देवबंद से है इसलिए हमें सऊदी सरकार के इस फैसले से बेहद परेशानी और चिंता हो रही है। तब्लीगी जमात के हितों की रक्षा करना हमारा दीनी कर्तव्य है। तब्लीगी जमात पर हमला दरअसल देवबंद पर हमला है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दुनिया में एक ऐसा वर्ग है जो इस्लाम के चिराग को बुझाना चाहता है और मेरा यह ईमान है कि यह चिराग नहीं बुझ सकता।

जमीयत उलेमा के दूसरे गुट के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने यह मत व्यक्त किया है कि सऊदी अरब के इस फैसले के पीछे कोई साजिश या राजनीतिक दबाव हो सकता है। हम इस साजिश को सफल नहीं होने देंगे। तब्लीगी जमात लोगों को नेक इंसान और सच्चा मुसलमान बनाने का काम कर रही है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा संगठन नहीं है जो उनके बराबर काम कर रहा हो। जनता दल (यूनाइटेड) के एमएलसी डॉ. खालिद अनवर ने सऊदी अरब द्वारा तब्लीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने की निंदा करते हुए कहा है कि यह इस्लाम विरोधी हरकत है। तब्लीगी जमात सिर्फ इंसान को इंसान और मुसलमान को सच्चा मुसलमान बनाने का काम करती है।

औरंगाबाद टाइम्स (14 दिसंबर) ने मुख्य समाचार के रूप में आठ कॉलमी समाचार प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, 'सऊदी अरब में तब्लीगी जमात पर प्रतिबंध इस्लाम के खिलाफ साजिश।' एक अन्य उपशीर्षक है, 'तब्लीगी जमात पर दहशतगर्दी का आरोप बेबुनियाद और भ्रामक। सऊदी अरब से निंदनीय फैसला वापस लेने की मांग।' युवराज मोहम्मद बिन सलमान इस्लामिक उसूलों और संस्कृति को मटियामेट कर रहे हैं। समाचारपत्र के अनुसार सऊदी सरकार ने तब्लीगी जमात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और तब्लीगी जमात को इस्लाम के खिलाफ विचारधारा फैलाने वाली, कब्रपरस्त और अतिवादी जमात की संज्ञा दी है। इस सिलसिले में देश भर के इमामों और खातिबों से आग्रह किया गया है कि वे जनता में इसके बारे में जागरूकता पैदा करें और तब्लीगी जमात से संबंधित व्यक्तियों से किसी भी तरह का संपर्क न रखें।

दारूल उलूम देवबंद के उलेमाओं ने सऊदी अरब के इस निर्णय पर चिंता प्रकट की है और गम व गुस्से का इजहार किया है और कहा है कि सऊदी अरब की इस निंदनीय कार्रवाई से अन्य मुल्कों में भी तब्लीगी जमात पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जो किसी तरह से ठीक नहीं होगा। सऊदी सरकार को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। दारूल उलूम देवबंद के मोहतमिम (कुलपति) मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने इस फैसले की निंदा करते हुए उस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है और कहा है कि तब्लीगी जमात के प्रवर्तक मौलाना मोहम्मद इल्यिास ने दारूल उलूम देवबंद से शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने तब्लीगी जमात स्थापित की। यह जमात अपने उद्देश्य पर कार्य कर रही है और सारी दुनिया में उसका नाम और काम फैला हुआ है। इसलिए उस पर इस्लाम के खिलाफ माहौल बनाने और आतंकवाद का आरोप लगाना सरासर बेबुनियाद है। दारूल उलूम इसकी निंदा करता है आर इस बात की आशा करता है कि सऊदी सरकार तब्लीगी जमात के खिलाफ किसी तरह का अभियान नहीं छेड़ेगी और पाबंदी को वापस ले लेगी।

जमात-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने भी तब्लीगी जमात के खिलाफ सऊदी सरकार के आदेश को गलत और अन्याय पर आधारित करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस्लामिक संगठनों को देश में अपनी गतिविधियों को जारी रखने की आजादी होनी चाहिए। यह शांतिपूर्ण संगठन है और इस्लाम के प्रसार व कल्याण के लिए कार्य करता है। एक प्रमुख मुस्लिम बुद्धिजीवी मौलाना उबैद इकबाल आसिम ने कहा है कि तब्लीगी जमात के खिलाफ सऊदी सरकार ने जो कदम उठाया है वह निंदनीय है। तब्लीगी जमात पूरी दुनिया में शांति आर भाईचारे का संदेश देती है और वह दीन और मस्जिदों से दूर लोगों को इस्लाम के नजदीक लाती है। अभी तक दुनिया में कोई सरकार तब्लीगी जमात पर उंगली नहीं उठा सकी। इसलिए ऐसा महसूस होता है कि सऊदी सरकार का यह फैसला इस्लाम के खिलाफ किसी बड़ी साजिश का नतीजा है।

देश के प्रमुख मुस्लिम विद्वान मौलाना नदीम अल-वाजिदी ने भी सऊदी सरकार के इस फैसले की निंदा की है और कहा है कि सऊदी सरकार से इस तरह के गैर जिम्मेवार कदम की किसी को उम्मीद नहीं थी। वहां के शासकों को मालूम होना चाहिए कि तब्लीगी जमात जैसे हक परस्त जमात के खिलाफ उन्होंने जो कदम उठाया है आलम-ए-इस्लाम में उसके क्या नतीजे होंगे? दुनिया के विभिन्न देश अब तब्लीगी जमात जैसे धार्मिक संगठनों को अपना निशाना बनाएंगे। मुफ्ती मोहम्मद शरीफ खान कासमी का कहना है कि सऊदी सरकार पूरी दुनिया के मुसलमानों की शुभचिंतक थी और वह विश्व स्तर पर इस्लाम के प्रचार व प्रसार के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती

थी मगर अब उसका रवैया न जाने क्यों बदल गया है। उन्होंने देश के मुस्लिम नताओं से अपील की कि वे तब्लीगी जमात के समर्थन में देश भर में आंदोलन चलाएं।

ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अहमद बेग नदवी ने सऊदी अरब के युवराज द्वारा उठाए गए इस तानाशाही फैसले की निंदा की है और कहा है कि आज तक किसी भी देश को तब्लीगी जमात से कोई शिकायत नहीं हुई, क्योंकि वह मुसलमानों और इस्लाम के कल्याण के लिए कार्य करती है। उन्होंने कहा है कि जब से मोहम्मद बिन सलमान युवराज बने हैं वे इस्लाम और इस्लामी सभ्यता को मटियामेट कर रहे हैं। कई प्रमुख मुस्लिम विद्वानों को जेलों में डाल दिया गया है। और कई मुस्लिम विद्वानों को फांसी पर लटका दिया गया है। इस्लामिक संस्कृति को मटियामेट करने के लिए देश में सिनेमाहॉल खोल दिए गए हैं और महिलाओं को वाहन चलाने की अनुमति दे दी गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे यहूदियों के हाथों में खेल रहे हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (13 दिसंबर) ने भी अपने मुख्य पृष्ठ पर एक समाचार प्रकाशित करके सऊदी सरकार से अनुरोध किया है कि वह तब्लीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करे क्योंकि तब्लीगी जमात आज तक शांति और सद्भावना का संदेश देती आ रही है और वह इस्लाम के प्रचार व प्रसार के लिए काम कर रही है। समाचारपत्र ने कहा है कि सऊदी अरब सरकार से इस फैसले की उम्मीद नहीं थी। इसलिए उस पर पुनर्विचार होना चाहिए।

इंकलाब (14 दिसंबर) ने तब्लीगी जमात पर लगाए गए प्रतिबंध पर भारतीय मुसलमानों के नेताओं की प्रतिक्रिया को मुख्य रूप से प्रकाशित किया है और इस बात पर संतोष प्रकट किया है कि सरकार की हिदायत के बावजूद मस्जिद नबवी के इमाम और काबा के इमाम ने अपने खुतबे में तब्लीगी जमात से संबंधित कोई बात नहीं कही है। नई दिल्ली स्थित सऊदी दूतावास ने इस संदर्भ में कोई खंडन जारी नहीं किया और न ही कोई पुष्टि की है। सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय व्यापारियों ने कहा है कि किसी भी मस्जिद के इमाम ने तब्लीगी जमात के बारे में वह खुतबा नहीं दिया है जिसका निर्देश सरकार ने उन्हें दिया था। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि सऊदी अरब में जानबूझकर यह प्रयास किया जा रहा है कि नई पीढ़ी को इस्लाम और उसकी संस्कृति से दूर किया जाए।

ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरात के अध्यक्ष नावेद हामिद ने सऊदी सरकार के इस फैसले पर लीपापोती करते हुए कहा है कि यह फैसला तब्लीगी जमात के खिलाफ नहीं है बल्कि अल-अहबाब नामक संगठन के खिलाफ है जिसकी गतिविधियों पर मस्जिदों में प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होनें कहा है कि अगर सऊदी सरकार के पास तब्लीगी जमात के खिलाफ कोई प्रमाण है तो उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि तब्लीगी जमात का आतंकवाद से दूर-दूर तक लेना-देना नहीं है। जमात-ए-इस्लामी के नायब अमोर प्रो. सलीम इंजीनियर ने भी सऊदी सरकार के फैसले पर टिप्पणी करने से इंकार करते हुए कहा है कि जब तक इस मामले की सरकारी तौर पर पुष्टि नहीं हो जाती तब तक मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जबकि आईओएस के चेयरमैन डॉ. मंजूर आलम ने तब्लीगी जमात पर लगाए गए प्रतिबंध की निंदा की है और कहा है कि इससे पहले भी सऊदी सरकार विभिन्न तब्लीगी संगठनों को अपना निशाना बनाती रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस्लाम के विभिन्न फिरकों में जो विवाद है उसके कारण इस प्रतिबंध को लगाया गया है। यह बात सरासर गलत है कि तब्लीगी जमात एक आतंकवादी संगठन है।

कांग्रेसी नेता मीम अफजल ने इस फैसले को आश्चर्यजनक और खेदजनक बताया है। उन्होंने

कहा है कि सऊदी सरकार को वह प्रमाण पेश करने चाहिए जिसके कारण यह प्रतिबंध लगाया गया है। उन्हें तब्लीगी जमात के लिए 'आतंकवाद का दरवाजा' जैसे शब्द इस्तेमाल करने से पूर्व यह सोचना चाहिए था कि इस कारण से हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए किस तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उन्होंने यह आशा व्यक्त की है कि सऊदी सरकार अपने इस फैसले को बदलेगी। शाही मस्जिद फतेहपुरी के इमाम सैयद मुकर्रम अहमद ने सऊदी सरकार के इस फैसले की निंदा की है और कहा है कि हालांकि वे तब्लीगी जमात के बारे में ज्यादा नहीं जानते मगर सऊदी अरब में इस्लाम के खिलाफ जिस तरह के अभियान चल रहे हैं उसके खिलाफ हर मुसलमान को अपनी आवाज उठानी चाहिए। वहां का दीनी माहौल समाप्त किया जा रहा है। जमीयत उलेमा के महामंत्री मुफ्ती अब्दुल रज्जाक ने सऊदी अरब के इस फैसले की निंदा करते हुए तब्लीगी जमात पर लगाए गए प्रतिबंधों को बेबुनियाद बताया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (14 दिसंबर) के अनुसार प्रमुख मुस्लिम विद्वान इब्राहिम खलील आबदी ने आरोप लगाया है कि सऊदी सरकार इस तरह की हरकतें करके अल्लाह के कहर को दावत दे रही है। उन्होंने कहा है कि आज मक्का और मदीना जैसे पवित्र स्थानों पर इजरायल की समर्थक सरकार का कब्जा है इसलिए इस कब्जे से मुक्ति के लिए मुसलमानों को विश्व भर में माहौल बनाना चाहिए।

बाबरी मस्जिद पुनर्निर्माण की जेएनयू में मांग

हालांकि प्रशासन ने बाबरी मस्जिद ध्वस्त किए जाने की बरसी के अवसर पर शांति व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए अनेक कदम उठाए थे। मगर इसके बावजूद दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वामपंथी छात्रों ने प्रशासन द्वारा लगाई गई प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाते हुए विश्वविद्यालय परिसर में उग्र प्रदर्शन किया और बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की मांग की।

मुंबई उर्दू न्यूज (8 दिसंबर) के अनुसार छात्र संघ की अपील पर गंगा ढाबा पर वामपंथी छात्र भारी संख्या में इकट्ठे हुए और वहां से प्रदर्शन करते हुए वे चद्रभागा होस्टल तक पहुंचे। छात्र बाबरी मस्जिद का पुराने स्थान पर ही पुनर्निर्माण की मांग कर रहे थे। वे नारे लगा रहे थे, 'नहीं सहेंगे हाशिमपुरा, नहीं करेंगे दादरी, फिर बनाओ, फिर बनाओ बाबरी।' इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए छात्रसंघ के उपाध्यक्ष साकेत मून ने आरोप लगाया कि सांप्रदायिक तत्वों ने धार्मिक भावनाओं को भड़काकर सांप्रदायिक दंगे करवाए हैं। जब तक बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण नहीं होता। हम चैन से नहीं बैठेंगे। छात्र संघ की अध्यक्ष आइशी घोष ने कहा कि बाबरी मस्जिद के बाद बीजेपी का अगला निशाना काशी है और उन्होंने इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। भाजपा और आरएसएस धर्म के नाम पर समाज को बांट रहे हैं।

इंकलाब (7 दिसंबर) के अनुसार बाबरी मस्जिद के यौमे शहादत पर वामपंथी और मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रकट करते हुए विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारी अपने हाथों में विभिन्न नारे व पास्टर लिए हुए थे और बाबरी मस्जिद की शहादत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। पटना में गांधी मैदान से लेकर कारगिल चौक तक प्रदर्शनकारियों ने जाम लगाया। राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर में पहली बार 'बाबरी मस्जिद यौमे शहादत' मनाया गया और दो मिनट का मौन रखा गया तथा इसे इतिहास का सबसे काला दिन बताया गया। एसडीपीआई ने बिहार में अनेक स्थानों पर प्रदर्शन किए। सीपीआईएमएल ने इसे भारतीय संविधान पर हमला करार दिया।

सियासत (7 सितंबर) के अनुसार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी अनेक स्थानों पर मुस्लिम संगठनों ने बाबरी मस्जिद शहादत दिवस मनाया।

मुंबई उर्दू न्यूज (7 दिसंबर) के अनुसार ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के महामंत्री डॉ. मंजूर आलम ने बाबरी मस्जिद की शहादत को इतिहास का काला पृष्ठ बताते हुए मुसलमानों से यह अपील की है कि अब काशी और मथुरा की मस्जिदों को भी बाबरी मस्जिद की तरह विवादित बनाने की जो कोशिश की जा रही है वह शर्मनाक है। सरकार और प्रशासन की यह जिम्मेवारी है कि वे कानून व्यवस्था पर काबू रखें और सभी शरारती तत्वों को गिरफ्तार करें जो देश के भाईचारे और शांति को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। ऐसे अवसर पर देश के सभी सेक्युलर हिंदुओं और मुसलमानों को सामने आना चाहिए और बाबरी मस्जिद की तरह पुनः कोई विवाद उत्पन्न करने के खिलाफ सख्ती से अभियान चलाना चाहिए। न्यायपालिका को चाहिए कि वह इस बात का संज्ञान ले और सरकार व प्रशासन को शरारत पसंदों के मंसूबों को विफल बनाने का निर्देश दे।

मुंबई उर्दू न्यूज (5 दिसंबर) के अनुसार बाबरी मस्जिद के यौमे शहादत पर मुंबई पुलिस ने मुस्लिम संगठनों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी और उन्हें किसी भी तरह का जलसा व जुलूस निकालने नहीं दिया। मगर रजा एकेडमी ने विरोध प्रकट करने के लिए विभिन्न मस्जिदों में अजान दी। वहादत इस्लामी, रजा एकेडमी, पॉपुलर फ्रंट आदि संगठनों ने भी विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी मगर पुलिस की सतर्कता के कारण उनकी हिम्मत नहीं हुई।

मुस्लिम संगठनों ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाने वाले पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को अपना निशाना बनाया है। इसके लिए उन्होंने जस्टिस रंजन गोगोई की पुस्तक 'जस्टिस फॉर द जज' का सहारा लिया, जिसमें यह दावा किया गया है कि अयोध्या विवाद का ऐतिहासिक फैसला सुनाने के बाद उन्होंने बेंच के अन्य न्यायाधीशों के साथ होटल ताज में चाइनिज फूड खाया और शराब पी। बाद में एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए जस्टिस रंजन गोगोई ने इस बात का खंडन किया कि इस फैसले का कोई जश्न नहीं मनाया गया था। मगर क्योंकि सभी न्यायाधीशों ने कई महीनों तक निरंतर कार्य किया था इसलिए आराम करने की खातिर हम इस पार्टी में शामिल हुए थे। उर्दू के विभिन्न समाचारपत्रों ने उनकी पुस्तक के विभिन्न अंशों को प्रकाशित किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की मांग की है।

मुंबई उर्दू न्यूज (7 दिसंबर) के संपादकीय में बाबरी मस्जिद की शहादत की निंदा करते हुए मुसलमानों से अपील की गई है कि वे अपने

आंदोलन को जारी रखें। समाचारपत्र ने कहा है कि मुसलमानों की कमजोरी को देखते हुए अब मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद में भी मूर्ति रखने की धमकियां दी जा रही हैं।

इत्तेमाद ने 5 दिसंबर के अंक में प्रकाशित एक संपादकीय में सरकार को चेतावनी दी है कि मुसलमान आने वाली नस्लों को यह संदेश देते रहेंगे कि बाबरी मस्जिद का कैसे शहीद किया गया था, ताकि उनके दिल में यह गम हमेशा ताजा रहे। समाचारपत्र ने कहा है कि बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए जितना जिम्मेवार हिंदू संगठन हैं उतना ही कांग्रेस भी है, क्योंकि कांग्रेस ने सेक्युलरिज्म का दंभ भरते हुए बाबरी मस्जिद की रक्षा का वायदा करके मुसलमानों की पीठ में खंजर घोंपा था। यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद के मामले को अपने राजनोतिक स्वार्थों के लिए जिंदा किया और बीजेपी ने उसे अंजाम तक पहुंचाया। समाचारपत्र ने कहा है कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो लोग यह समझ रहे थे कि यह मामला शायद यहीं रूक जाएगा वह उनकी कल्पना थी। क्योंकि राम मंदिर के बाद अब भगवा जमात ने काशी, मथुरा और अन्य मस्जिदों को भी अपने निशाने पर ले लिया है। हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हमारी मस्जिदें आबाद रहें और उनमें हम अधिक से अधिक संख्या में नमाज अदा करें।

इस्लाम के प्रचार के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान

देश के विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने इस्लाम के प्रचार-प्रसार के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ दिया है।

सियासत (7 दिसंबर) के अनुसार जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने इस बात पर जोर दिया है कि इस्लाम से संबंधित साहित्य को अधिक-से-अधिक संख्या में हिंदी भाषा में पेश किया जाए ताकि इस्लाम की दावत आम हिंदुस्तानियों तक पहुंच सके। मौलाना मदनी ने दावा किया कि आठ वर्ष के प्रयास के बाद उन्होंने कुरान का हिंदी में अनुवाद पेश किया है। इसकी परिभाषा भी सरल शब्दों में पेश की गई है ताकि आम लोग जो मुसलमान नहीं हैं वे भी कुरान शरीफ के संदेश को समझ सकें और इस्लाम की दावत का अधिक से अधिक प्रचार एवं प्रसार हो। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ियां उर्दू भाषा से दूर होती जा रही हैं इसलिए उन्हें इस्लाम का संदेश देने के लिए जरूरी है कि इस्लामिक पुस्तकों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हिंदी भाषा में पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि कुरान अरबी भाषा में नाजिल हुआ था मगर जब इस्लाम का प्रसार हुआ तो इस बात को समझा गया कि इस्लाम के संदेश को गैर मुसलमानों तक पहुंचाने के लिए उनकी मातृभाषाओं में पेश किया जाए। इसी उद्देश्य से भारत के उलेमा ने कुरान का अनुवाद फारसी भाषा में किया। बाद में इसे जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए शाह वली उल्लाह ने उसका उर्दू अनुवाद करके उसे भारतीयों तक पहुंचाया। मोहम्मद हुसैन मदनी और मौलाना थानवी ने कुरान का अनुवाद सरल उर्दू में पेश किया। अब क्योंकि हिंदी का चलन बढ़ रहा है इसलिए यह जरूरी है कि इस्लाम के प्रचार के लिए हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का सहारा लिया जाए। यही कारण है कि आठ वर्ष के बाद सरल हिंदी में कुरान और उसकी परिभाषा को पेश किया गया है।

सालार (1 दिसंबर) के अनुसार जमात-ए-इस्लामी ने भी इस बात की घोषणा की है कि उसके कार्यकर्ता घर-घर जाएंगे और गैर मुसलमानों तक कुरान और रसूल का संदेश पहुंचाएंगे। यह अभियान देश के विभिन्न राज्यों में शुरू कर दिया गया है। इस उद्देश्य से इस्लाम से

संबंधित साहित्य हिंदी के अतिरिक्त एक दर्जन अन्य भारतीय भाषाओं में भी तैयार किया गया है, जिसका नि:शुल्क वितरण जमात के कार्यकर्ता करेंगे। जमात-ए-इस्लामी के सूत्रों के अनुसार इस समय यह अभियान देश के सात राज्यों में पूरी गति से चल रहा है।

एक अन्य संगठन पॉपुलर फ्रंट ने 'इस्लामिक योद्धा' नामक एक वीडियो में इस बात की घोषणा की है कि पूर्वोत्तर भारत, असम और पश्चिम बंगाल आदि में गैर मुसलमानों को इस्लाम की ओर आकर्षित करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस संदर्भ में अनेक वीडियो भी तैयार किए गए हैं जिनमें पॉपुलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं को इस्लाम से संबंधित साहित्य गैर मुसलमानों के घर-घर जाकर नि:शुल्क वितरीत करते हुए दिखाया गया है।

मुंबई की रजा एकेडमी ने भी इस्लाम की दावत का काम बड़े व्यापक पैमाने पर शुरू किया है। इस संगठन द्वारा यह कार्यक्रम राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में पूरी गति से चलाए जाने का दावा किया गया है। जमीयत उलेमा ने सभी मस्जिदों के इमामों से यह आग्रह किया है कि वे गैर मुसलमानों के लिए मस्जिदों के दरवाजे खोल दें और उनसे नजदीकी संबंध बढ़ाएं ताकि उनमें इस्लाम का प्रसार किया जा सके।

इंकलाब (25 नवंबर) के अनुसार दारूल उलूम देवबंद ने सभी इस्लामिक मदरसों के प्रबंधकों से आग्रह किया है कि वे अपने कार्यक्रमों में गैर मुसलमानों को ज्यादा-से-ज्यादा संख्या में आमंत्रित करें ताकि वे इस्लाम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और वे इस्लाम के नजदीक आएं।

मथुरा की ईदगाह का मामला उठाने की तैयारी

इंकलाब (2 दिसंबर) ने यह आरोप लगाया है कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश के आने वाले विधान सभा चुनाव से पूर्व धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिशें तेज कर दी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हुए कुछ बड़े नेता इस तरह की हरकतें और बयान दे रहे हैं जो राज्य में शांति व्यवस्था के लिए खरतनाक सिद्ध हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्विट में मथुरा की तैयारी का राग अलापकर अतिवादी हिंदू वोटरों को लुभाने की कोशिश की है और विपक्षी दलों ने उन पर हल्ला बोल दिया है। वे इसे योगी बनाम केशव के शीतयुद्ध का नतीजा भी बता रहे हैं। राज्य के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्विट में लिखा है, 'अयोध्या, काशी में मंदिर का निर्माण जारी है अब मथुरा की बारी है।' उनके इस बयान पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा

अपनी संभावित हार से घबरा गई है और वह चुनाव से पूर्व धार्मिक आधार पर वोटरों का ध्रुवीकरण चाहती है। कांग्रेस प्रवक्ता सरेन्द्र सिंह राजपूत ने इंकलाब को बताया कि बीजेपी और केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग आने वाली हार को भांप चुके हैं। उन्हें यह पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पांच वर्ष और मोदी सरकार के आठ वर्ष पूर होने वाले हैं। जबकि उपलब्धि के नाम पर दिखाने के लिए उनक पास कुछ नहीं है। इसलिए

जनता का ध्यान भटकाने के लिए वे मथुरा की ईदगाह का मामला उठाने की तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुमैया राना का कहना है कि इस तरह के मुद्दे इसलिए उछाले जा रहे हैं ताकि जनता का ध्यान सरकार की विफलताओं से हटाया जा सके। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की बुद्धिजीवी सेल के अध्यक्ष । दीपक मिश्रा ने कहा है कि जनता की समस्याओं का समाधान करने की बजाय भाजपा लोगों को मंदिर और मस्जिद में ही उलझाए रखना चाहती है।

इसी अंक में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार प्रशासन के सख्त रूख को देखते हुए मथुरा की ईदगाह मस्जिद पर विवाद खड़ा करने वाले हिंदू संगठनों ने अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने अपने ट्विट में कहा है कि प्रशासन ने क्योंकि उन्हें कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी है इसलिए उसे रद्द किया जा रहा है। वहीं इस संगठन के जिलाध्यक्ष छाया गौतम ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया गया है कि छह दिसंबर को वे अपने घरों में जलाभिषेक कर लें। राजश्री का दावा है कि गौतम से पुलिस ने यह वीडियो बयान जबरन जारी करवाया है क्योंकि वह उनकी हिरासत में थीं। मथुरा में धारा 144 लागू करने के साथ-साथ जिला प्रशासन और पुलिस ने कड़ा रूख अपनाया है। नारायणी सेना से संबंधित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें ऋषि उपाध्याय भी शामिल है। हिंदू महासभा और इस संगठन ने ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक के साथ-साथ संकल्प यात्रा निकालने की घोषणा की थी।

सियासत (8 दिसंबर) ने यह आरोप लगाया है कि योगी सरकार मंदिर मस्जिद के एजेंडे पर वापस आ गई है। उत्तर प्रदेश क मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने मुसलमानों से अपील की है कि वे मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर के समीप वाली मस्जिद को हिंदुओं के हवाले कर दें। उन्होंने कहा है कि अदालत ने अयोध्या समस्या का समाधान कर दिया है। लेकिन वाराणसी और मथुरा के ढांचे हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं। शुक्ला ने कहा है कि डॉ. राममनोहर लोहिया ने कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह मानना होगा कि राम व कृष्ण उनके पूर्वज थे और बाबर, अकबर और औरंगजेब आक्रांता। इसलिए उनके द्वारा बनाए गए किसी भी भवन के साथ मुसलमान अपन आप को न जोड़ें। मुस्लिम बिरादरी को स्वयं आगे बढ़कर श्रीकृष्ण मंदिर पर

बने हुए ढांचे को हिंदुओं के हवाले कर देना चाहिए।

सियासत (8 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में केशव प्रसाद मौर्य और आनंद स्वरूप शुक्ला के बयानों की निंदा की है और कहा है कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है और हर तरफ से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कट्टरपंथ का चेहरा बन चुके हैं और अब उनके उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी किसी से पीछे रहने के लिए तैयार नहीं हैं। एक ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की समस्या राजनीतिक दृष्टि से समाप्त हो चुकी है अब मथुरा का मामला उठाने का प्रयास किया जा रहा है। यह मामला पार्टी में अपने सियासी कद को बढ़ाने के लिए उठाया जा रहा है।

मुंबई उर्दू न्यूज (3 दिसंबर) ने अपने मुख्य समाचार का शीर्षक दिया है, 'मथुरा शाही ईदगाह को गंगाजल से शुद्ध करने का नापाक मंसूबा।' 'मस्जिद में मूर्ति स्थापित करने का हिंदू संगठनों का शरारती ऐलान।' 'सारे क्षेत्र में धारा 144 लागू।' समाचारपत्र ने कहा है कि प्रशासन ने शरारती तत्वों को कुचलने के लिए सख्त कदम उठाए हैं और वहां पर सुरक्षा बलों के कड़े पहरे की व्यवस्था की गई है। मथुरा में चार अतिवादी हिंदू संगठन जिनमें हिंदू महासभा, कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास, नारायणी सेना और श्रीकृष्ण मुक्ति दल शामिल हैं ने मस्जिद में लड्डू गोपाल की मूर्ति को स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। इन संगठनों का दावा है कि जिस स्थान पर मस्जिद है वहीं भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था। प्रशासन ने सख्त कदम उठाकर उनके इस प्रयास को विफल बना दिया है।

इत्तेमाद (9 दिसंबर) के अनुसार भाजपा उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए फिर से मंदिर का सहारा ले रही है और इस लक्ष्य से मथुरा के मुद्दे को उछाला जा रहा है।

इत्तेमाद के 5 दिसंबर के अंक में सिराज नकवी ने अपने लेख में यह आरोप लगाया है कि अब भाजपा सत्ता प्राप्ति के लिए मथुरा का सहारा ले रही है।

इस्लाम छोड़कर सनातन की शरण में

रोजनामा सहारा (7 दिसंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को स्वीकार करने की घोषणा की है। इस संदर्भ में उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। रिजवी ने कहा है कि क्योंकि मुझे इस्लाम से निकाल दिया गया है इसलिए मैं सनातन धर्म की शरण में गया हूं जो कि दुनिया का सबसे पहला धर्म है और इसमें इतनी अच्छाईयां है जितनी किसी धर्म में नहीं है। उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया है कि कट्टरपंथियों द्वारा जुमे की हर नमाज में मेरे और यति नरसिंहानंद सरस्वती के सिर पर इनाम की रकम बढ़ा दी जाती है। इस पर नरसिंहानन्द सरस्वती ने कहा कि अब रिजवी का नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी होगा। गौरतलब है कि रिजवी शुरू से ही विवादित रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कुरान से 26 विवादित आयतों को खारिज करने की घोषणा की थी और एक विवादित पुस्तक 'मोहम्मद' भी लिखी है। रिजवी का दावा है कि कट्टरपंथी मुसलमान उनकी हत्या करना चाहते हैं। शिया समाज इससे पहले ही रिजवी को इस्लाम से खारिज कर चुका है।

मुंबई उर्दू न्यूज (7 दिसंबर) के अनुसार रिजवी के धर्मांतरण के लिए डासना स्थित देवी मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें हवन हुआ। वसीम रिजवी ने पूजा में भाग लिया और शिवलिंग पर दूध भी चढ़ाया।

मुंबई उर्दू न्यूज (12 दिसंबर) के अनुसार मलयालम फिल्म निर्देशक अली अकबर ने यह घोषणा की है कि वे और उनकी पत्नी इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपना रहे हैं। अली अकबर ने इस्लाम धर्म छोड़ने की अजीब वजह बताई है। उन्होंने कहा कि वे और उनकी पत्नी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपीन रावत और उनकी पत्नी की दुर्भाग्यपूर्ण मौत पर सोशल मीडिया पर एक वर्ग द्वारा खुशी मनाए जाने के विरोध में इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म स्वीकार कर रहे हैं। उन्हांने कहा कि उनकी दोनों पुत्रियां आजाद हैं वे चाहें इस्लाम में रहें या न रहें।

मुंबई उर्दू न्यज (3 दिसंबर) के अनुसार बरेली शरीफ दरगाह के एक प्रतिनिधिमंडल ने बरेली के जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह से भेंट करके उनसे मांग की है कि वसीम रिजवी क्योंकि खुलेआम हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं इसलिए उनकी पुस्तक को जब्त करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन पर देशद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया जाए। रजा एकेडमी के महासचिव मोहम्मद सईद नूरी ने यह मत व्यक्त किया है कि वसीम रिजवी किसी विदेशी शक्ति के इशारे पर देश में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (12 दिसंबर) के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जिसमें अदालत से यह मांग की गई है कि वसीम रिजवी के इस्लाम विरोधी बयानों पर प्रतिबंध लगाया जाए क्योंकि इससे समाज में अशांति फैल सकती है। यह याचिका ख्वाजा गरीब नवाज एसोसिएशन के सचिव मोहम्मद युसूफ अंसारी की ओर से दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि वसीम रिजवी अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए कुरान और पैगंबर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने यह घोषणा की है कि उनका अंतिम संस्कार एक हिंदू के तौर पर किया जाए। इससे मुसलमानों में काफी बेचैनी है।

विश्व

कुरान के कथित अपमान के आरोप में श्रीलंकाई को जीवित जलाया

इत्तेमाद (4 दिसंबर) के अनुसार पाकिस्तान के सियालकोट में एक कपड़ा फैक्ट्री के महाप्रबंधक को कुरान के कथित अपमान के आरोप में उग्र भीड़ ने जीवित जला दिया। बताया जाता है कि प्रियंथा कुमारा नामक व्यक्ति जिनकी उम्र 49 वर्ष के लगभग थी गत पांच वर्षों से कपड़ों की एक फैक्ट्री में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। बताया जाता है कि फैक्ट्री में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने कुछ पोस्टर लगाए थे जिन पर कुरान की आयतें लिखी हुई थीं। इस व्यक्ति ने अपने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे इन पोस्टरों को उतार दें। जब वे इन पोस्टरों को उतारने के लिए तैयार नहीं हुए तो उन्होंने स्वयं इन पोस्टरों को उतारकर फाड़ दिया। जब यह बात फैक्ट्री में फैल गई तो मजदूरों ने बाहर जाकर इलाके में शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद हजारों उग्र लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। कुमारा अपनी जान बचाने के लिए एक कमरे में छिप गए। मगर उनके कर्मचारियों ने उन्हें वहां से निकालकर भीड़ के हवाले कर दिया। भीड़ ने उन्हें बुरी तरह से पीटा और उसके बाद उन पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। इस घटना का वीडिया सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और उसने स्थिति पर काबू पाने का प्रयास किया। जब पुलिस स्थिति पर काबू पाने में विफल रही तो सेना और अर्द्धसैनिक दस्तों की सहायता ली गई। इसके बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रशासन को यह निर्देश दिया कि इस घटना के दोषियों को गिरफ्तार किया जाए।

रोजनामा सहारा (5 दिसंबर) के अनुसार पाकिस्तानी समाचारपत्र 'डॉन' के अनुसार पुलिस ने इस फैक्ट्री के 900 कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और। सियालकोट पुलिस ने जिले के अनेक गांवों और कस्बों पर छापे मारकर 235 लोगों को गिरफ्तार किया है और राजको इंड्स्ट्रीज नामक इस कारखाने को बंद कर दिया

गया है। सियालकोट के उपायुक्त ताहिर फारूक ने संवाददाताओं को बताया कि किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कुमारा की लाश को कोलंबो भेज दिया गया है।

इमरान खान ने घोषणा की है कि जब पाकिस्तान में रसूल कुरान का अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानून मौजूद है तो ऐसी स्थिति में भीड़ की इस हरकत को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। समाचारपत्रों के अनुसार सबसे पहले कुमारा को उनकी फैक्ट्री के कर्मचारियों ने ही पीटना शुरू किया था। बाद में जब यह समाचार फैला तो आसपास के क्षेत्रों से लोग इकट्ठे होकर फैक्ट्री पर पहुंच गए।

अवधनामा (5 दिसंबर) के अनुसार श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने सियालकोट की घटना की निंदा की है और यह विश्वास प्रकट किया है कि इमरान खान अपने वायदे को निभाएंगे और किसी भी दोषी को नहीं बख्शेंगे। उन्होंने मारे गए व्यक्ति के परिवारजनों से संवेदना व्यक्त की है। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने इस घटना की निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उन्हें फांसी पर लटकाने की मांग की है।

सियासत (8 दिसंबर) के अनुसार इस्लाम के विभिन्न फिरकों के उलेमाओं ने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि इस्लाम नबी के नाम की आड़ में वे किसी व्यक्ति पर कभी जुल्म नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के विभिन्न इस्लामिक संगठनों की अपील पर 10 दिसंबर को देश भर में 'निंदा दिवस' मनाया गया। सियालकोट के फैक्ट्री वालों ने एक लाख डॉलर की धनराशि कुमारा के परिजनों को देने की घोषणा की है। ■

म्यांमार की अपदस्थ प्रधानमंत्री को चार वर्ष की सजा

मुंबई उर्दू न्यूज (7 दिसंबर) क अनुसार म्यांमार की एक अदालत ने म्यांमार की अपदस्थ प्रधानमंत्री आंग सान स की को 4 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। उन पर लोगों को हिंसा के लिए भड़काने और कोविड नियमों के उल्लंघन का आरोप है। म्यांमार में सैनिक विद्रोह के बाद सू की के खिलाफ यह पहला निर्णय है। हाल ही में म्यांमार के पूर्व राष्ट्रपति विन मिंट को भी इन्हीं आरोपों में चार वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि म्यांमार में सैनिक कार्रवाई के बाद सू की और उनके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें अभी तक उनके घर में ही नजरबंद रखा गया है। सैनिक क्रांति के खिलाफ अभी म्यांमार के विभिन्न क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला थम नहीं रहा है। म्यांमार की सैनिक सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि अभी

पुराने मंत्रियों के खिलाफ अन्य आरोपों में भी कार्रवाई की जाएगी। ब्रिटेन ने सू की को सजा सुनाए जाने की निंदा करते हुए उसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया है और कहा है कि निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की गिरफ्तारी से देश में और अधिक अशांति फैल सकती है। उन्होंने सेना के अधिकारियों से अपील की है कि वे सभी

राजनीतिक बंदियों को रिहा करें और देश में लोकतंत्र लाने के लिए ठोस कदम उठाएं। अदालत में यह आरोप लगाया गया है कि सू की के समर्थकों ने सेना के खिलाफ फेसबुक से ऐसी पोस्ट की जिनसे जनता को सैनिक अधिकारियों के खिलाफ भड़काया गया।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष नवंबर महीने में हुए चुनावों में सू की और उनके सहयोगी चुनाव जीत गए थे। जबकि सेना की समर्थक पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी। हारने वाली पार्टी ने यह आरोप लगाया था कि यह चुनाव धांधली से जीते गए हैं। इसके बाद सेना ने विद्रोह करके सू की और उनके सहयोगी राजनेताओं को गिरफ्तार करके उनको घरों में नजरबंद कर दिया था। सू की के समर्थकों का कहना है कि वे और पूर्व राष्ट्रपति हिरासत में हैं ऐसी स्थिति में वे लोगों को उकसाने के लिए फेसबुक पर पोस्ट कैसे करवा सकते हैं? विशेष अदालत का यह फैसला एक अधिकारी ने बाद में पत्रकारों को सुनाया। मगर उसने अपनी पहचान को गुप्त रखने की भी अपील की है। इस फैसले के बाद सू की दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकेगी। सू की और अन्य सहयोगियों को कैद की सजा मिलने के बाद जन प्रदर्शनों में और भी तेजी आई है। ■

यूक्रेन पर हमला किया तो रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी

सियासत (14 दिसंबर) के अनुसार दुनिया के शक्तिशाली देशों के समूह जी-7 ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी गुप्तचर विभाग ने यह अंदाजा लगाया है कि रूस नए वर्ष की शुरुआत में यूक्रेन पर हमला कर सकता है और इस हमले के लिए उसने यूक्रेन की सीमाओं पर पौने दो लाख सैनिक इकट्ठे कर रखे हैं। रूस क रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पश्चिमी देश रूस फोबिया का शिकार हैं और नाटो को रूस से खतरा नजर आ रहा है। ब्रिटेन के लिवरपूल में हुए जी-7 देशों के अधिवेशन में यूक्रेन की सीमा के समीप रूस के सैनिक अभ्यासों की निंदा की है और रूस को चेतावनी

दी है कि वह इस तरह की भड़काऊ गतिविधियां बंद करे। उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय एकता की हर कीमत पर रक्षा करेंगे।

दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस को इस बात की गारंटी दी जाए कि नाटो शक्तियां पूर्व में अपना विस्तार नहीं करेंगी और न ही अपने अस्त्र-शस्त्रों को रूस के समीप इकट्ठा करेंगी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति को यह स्पष्ट शब्दों में बताया ह कि रूस का इरादा किसी भी देश पर हमला करने का नहीं है। उसन अपनी सेना अपनी ही सीमा पर इकट्ठा की है। मगर उन्हें अपराधी के रूप में पेश किया जा रहा है। गौरतलब है कि जी-7 में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका के साथ-साथ यूरोपीय यूनियन भी शामिल हैं।

इंकलाब (7 दिसंबर) के अनुसार अमेरिका ने यह दावा किया है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और उसने उसकी सीमा के समीप चार स्थानों पर पौने दो लाख रूसी फौजी इकट्ठे किए हैं जो कि टैंकों और तोपखानों से लैश हैं। यूक्रेन के रक्षामंत्री ने यह संभावना व्यक्त की है कि रूस अगले महीने उनके खिलाफ सैनिक कार्रवाई कर सकता है। गौरतलब है कि 2014 में क्रीमिया के रूस में विलय और यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र डोनबास में विद्रोहियों के विद्रोह के बाद रूस द्वारा उनका समर्थन करने के कारण रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ा है।

इंकलाब (21 दिसंबर) के अनुसार ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर मास्को ने यूक्रेन पर दोबारा हमला किया तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटेन ने जी-7 के देशों से अपील की है कि वे रूस के खिलाफ एकजुट हो जाएं।

यूक्रेन और रूस के बढते हुए तनाव पर प्रकाश डालते हुए **सियासत** ने 11 दिसंबर के एक संपादकीय में कहा है कि अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों के बीच दो घंटे तक वीडियो वार्ता हुई थी जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर रूस ने यूक्रेन में हस्तक्षेप किया तो अमेरिका पूर्वी यूरोप को सैनिक सहायता बढ़ा देगा और रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाएंगे। जबकि रूसी राष्ट्रपति ने इस आरोप का खंडन किया है मगर सैटेलाइट चित्रों से यह साफ होता है कि यूक्रेन की सीमा पर रूसी सैनिक भारी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं और वे तोपखाना और टैंकों से लैश हैं। इससे विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो गया है।

गौरतलब है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने वाला नहीं है मगर इसके बावजूद रूस के राष्ट्रपति इस संबंध में आश्वासन चाहते हैं जो कि उन्हें मिलने वाला नहीं है। जर्मनी के नए चांसलर ने चेतावनी दी है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रूस और चीन के कारण अमेरिका के संबंधों में जो तनाव आ रहा है वह विश्व के लिए परेशानी का कारण है। यह समय की मांग है कि इस तनाव को और बढ़ाया न जाए। समाचारपत्र ने यह लिखा है कि अमेरिका और यूरोपीय देश 2014 से यूक्रेन को सैनिक सहायता दे रहे हैं ताकि अगर रूस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके।

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति डांवाडोल

सियासत (4 दिसंबर) के अनुसार पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ रही है। पाकिस्तान के शेयर बाजार में हाल ही में इस वर्ष की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। पाकिस्तानी शेयर बाजार के सूचकांक में 2135 अंक की गिरावट आई है। अर्थात बाजार में उपलब्ध पूंजी 5 प्रतिशत कम हो गई है। दूसरी ओर आयात में वृद्धि हुई है जबकि निर्यात में कमी के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अस्थिर हो गई है। आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान के शेयर बाजार के इतिहास में यह तीसरी सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले ऐसी गिरावट 16 मार्च 2020 को देखी गई थी जब एक ही दिन में बाजार में 2376 अंक की गिरावट आई थी। जबकि 24 मार्च 2020 को भी बाजार में 2103 अंक की गिरावट देखी गई थी। आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि बाजार में आई गिरावट गिरती हुई अर्थव्यवस्था का संकेत है और इसके कारण पाकिस्तान में पूंजी निवेशकों की रुचि को भी भारी धक्का लगा है।

पाकिस्तान के स्पेक्ट्रम सेक्युरिटीज के अनुसंधान प्रमुख अब्दुल अजीम के अनुसार शेयर बाजार में गिरावट से देश के आर्थिक ढांचे में सबसे बड़ा घाटा सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान को सिर्फ एक महीने में पांच अरब डॉलर से भी अधिक व्यापारिक घाटे का सामना करना पड़ा है जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए जबर्दस्त झटका है। आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान ने नवंबर महीने में 8 अरब डॉलर का माल बाहर से मंगवाया। जबकि इस अवधि में सिर्फ दो अरब 90 करोड़ डॉलर का माल ही बाहर भेजा। इस तरह से चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों में पाकिस्तान को 20 अरब 75 करोड़ डॉलर का व्यापारिक घाटा हुआ है जो गत वर्ष इस अवधि में हुए घाटे स 117 प्रतिशत अधिक है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस वर्ष के अंत तक पाकिस्तान का आर्थिक घाटा 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।

मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में 12 वर्ष की सजा

रोजनामा सहारा (9 दिसंबर) के अनुसार मलेशिया क उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को भ्रष्टाचार के आरोप में एक अदालत द्वारा दी गई 12 वर्ष कैद की पुष्टि की है। उन पर सरकारी फंड को लूटने का आरोप है। पिछले वर्ष जुलाई में एक अदालत ने उन्हें सरकारी विकास फंड में भ्रष्टाचार के आरोप में 12 वर्ष कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले को उन्होंने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उन पर सरकारी फंड से करोड़ों के गबन के अतिरिक्त सरकारी अधिकारों के दुरुपयोग, मनो लॉंडिंग के आरोपों में कई मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से सिर्फ एक मुकदमे में ही उन्हें 12 वर्ष कैद के साथ-साथ 50 लाख अमेरिकी डॉलर के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की थी। इन दिनों वे जमानत पर हैं। उनकी पत्नी के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमे चल रहे हैं। क्योंकि उनके वकील कोविड महामारी से पीड़ित हैं इसलिए अदालत ने अपना फैसला वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा सुनाया है। फैसले के बाद उनके वकील शाफी अब्दुल्लाह ने कहा कि वे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे। रजाक का यह कहना है कि यह रकम उन्हें सऊदी अरब के राजपरिवार ने सहायता के रूप में दी थी। लेकिन जज अब्दुल करीम ने उनके इस तर्क को खारिज कर दिया। अदालत ने सातों आरोपों को बरकरार रखा है।

गौरतलब है कि नजीब रजाक ने 2009 में सत्ता में आने के बाद मलेशिया में आर्थिक विकास की परियोजनाओं के लिए पूंजी प्राप्त करने के उद्देश्य से एसआरसी इंटरनेशनल कंपनी कायम की थी। बाद में यह कंपनी अरबों डॉलर के कर्ज में फंस गई। जांचकर्ताओं ने यह आरोप लगाया था कि इस फंड से साढ़े सात अरब डॉलर का गबन किया गया है। नजीब के सहयोगियों ने इस धनराशि का पूंजी निवेश हॉलीवुड में फिल्म बनाने, होटल खरीदने और 250 मिलियन डॉलर का एक जलयान, जेवरात और पिकासो की एक पेंटिंग खरीदने के लिए किया। इसके अतिरिक्त एक अरब डॉलर गैर कानूनी ढंग से नजीब के खातों में हस्तांतरित की गई। नजोब की पत्नी और उनक दल के कई अन्य पदाधिकारियों पर भी रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। ■

पश्चिम एशिया

सऊदी अरब में तब्लीगी जमात पर प्रतिबंध

सियासत (11 दिसंबर) के अनुसार सऊदी अरब सरकार ने तब्लीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है और उसे समाज के लिए खतरा एवं आतंकवाद का दरवाजा करार दिया है। सऊदी अरब के इस्लामिक मामलां के मंत्री डॉ. अब्दुल लतीफ अल-शेख ने सभी मस्जिदों के इमामों को यह निर्देश दिया है कि वे जुमा की नमाज के बाद अपने अपन खुतबे में नमाजियों को तब्लीगी जमात या अल-अहबाब के खिलाफ जागरूक करं। इस संबंध में 6 दिसंबर को सऊदी सरकार ने एक ट्विट भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि यह संगठन दिशाभ्रमित है और इस्लाम के रास्ते से हट गया है। इसलिए यह समाज के लिए बेहद खतरनाक है। हालांकि यह संगठन इस बात को स्वीकार नहीं करता मगर यह हकीकत है कि यह संगठन आतंकवाद का दरवाजा है। सरकार उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है और उनके कारण समाज को होने वाली क्षति का भी विश्लेषण कर रही है। सरकारी तौर पर इस बात की पुष्टि की गई है कि इन पर सऊदी अरब में पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा चुका है। जानकार सूत्रों का अनुमान है कि सऊदी सरकार इस संगठन से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ जबर्दस्त अभियान छेड़ने की तैयारी कर रही है।

खास बात यह है कि हमारे देश के अधिकांश उर्दू और विशेष रूप से मुसलमानों द्वारा संचालित समाचारपत्रों ने सऊदी अरब सरकार द्वारा तब्लीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने की खबर को छिपाने की कोशिश की। जब देश के अन्य समाचारपत्रों ने इस समाचार को प्रकाशित किया तो एक सप्ताह के बाद कुछ उर्दू समाचारपत्रों ने इसे प्रकाशित किया।

बेंगलुरु से प्रकाशित समाचारपत्र **सालार** ने 12 दिसंबर को इसे प्रकाशित किया है और इस बात पर जोर दिया है कि सऊदी सरकार ने धार्मिक नेताओं और इस्लाम के विद्वानों पर इस बात के लिए दबाव डाला है कि वे जनता को यह बताएं कि तब्लीगी जमात और उससे संबंधित ग्रुप

समाज के लिए कितना खतरनाक हैं। यह जमात कितनी बड़ी है इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि विश्व भर में इसके 35-40 करोड़ सदस्य फैले हुए हैं। सऊदी सरकार का कहना है कि वैसे तो यह संगठन यह दावा करता है कि उसकी गतिविधियां सिर्फ धर्म तक ही सीमित है और वह राजनीति और आतंकवाद से दूर रहता है। लेकिन इसके ये दावे पूरी तरह से खोखले हैं।

औरंगाबाद टाइम्स ने 13 दिसंबर के अंक में यह समाचार एएनआई के हवाले से प्रकाशित किया है और कहा है कि सऊदी सरकार ने तब्लीगी जमात से संबंधित लोगों को यह निर्देश दिया है कि वे सऊदी अरब की सभी मस्जिदों को खाली कर दें और जनता को भी यह कहा गया है कि वे इस संगठन से संबंधित लोगों से किसी प्रकार का संपर्क न रखें।

गौरतलब है कि भारत में कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने यह आरोप लगाया था कि तब्लीगी जमात के दिल्ली स्थित मुख्यालय में आने वाले लोगों के कारण कोरोना की महामारी देश में फैली है। हालांकि अदालतों में इस आरोप को सरकार सिद्ध करने में विफल रही है।

क्या है तब्लीगी जमात?

अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी सीआईए के अनुसार तब्लीगी जमात विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक संगठन है जो कि जिहादियों की फौज तैयार करता है। इसकी शाखाएं इस समय विश्व के 150 से अधिक देशों में फैली हुई हैं और इसके अनुयायियों की संख्या 30-40 करोड़ के बीच बताई जाती है। इस संगठन का दावा है कि उनके प्रयासों से 25 करोड़ से अधिक गैर मुसलमानों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया है। इस संगठन के प्रयास से जो लोग इस्लाम में परिवर्तित हुए हैं उनमें से अधिकांश का संबंध यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और अन्य एशियाई देशों से है। इससे संबंधित जिहादी संगठनां में अलकायदा, बोको हराम, अल-अंसार, तालिबान, जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा, लश्कर-ए-झंगवी, सिपाह-ए-सहाबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-अहबाब, तहरीक-ए-लब्बैक आदि कई दर्जन संगठन शामिल हैं।

खास बात यह है कि पिछले दिनों जब संगठन दो समानांतर गुटों में बंट गया था तो इस्लामिक जगत के विभिन्न देशों के प्रमुख विद्वानों ने इस संगठन में एकता स्थापित करने के लिए जोरदार प्रयास किया था।

ब्रिटिश समाचारपत्र **सिक्यूरिटी विकली** (23 जनवरी, 2008) में यूरोप के दो प्रमुख खोजी पत्रकारों फ्रेड बर्टन और स्कॉट स्टूअर्ट ने एक विशेष रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि स्पेन की पुलिस ने बार्सिलोना नगर में एक मस्जिद पर छापा मारकर तब्लीगी जमात के 14 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था और उनके कब्जे से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ और अस्त्र-शस्त्र बरामद हुए थे। फ्रांस के तत्कालीन गृहमंत्री ने कहा था कि पकड़े गए लोगों का संबंध आतंकवादी इस्लामिक संगठन तब्लीगी जमात से है। पकड़े गए लोगों में 12 पाकिस्तानी, एक भारतीय और एक बांगलादेशी मूल का आतंकवादी शामिल था। 2006 में लंदन हवाई अड्डे पर जो धमाका हुआ था उसमें भी इसी जमात का हाथ पाया गया था। इसके बाद 2007 में लंदन और ग्लासगो में हुए बम विस्फोटों के तार भी इसी संगठन से जुड़े हुए थे। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले और 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले क पीछे भी जिन आतंकवादियों का हाथ था उनके तार भी तब्लीगी जमात से जुड़े हुए थे। पाकिस्तान में पेशावर और बलूचिस्तान में हुए आतंकी हमलों में भी इसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोगों का हाथ पाया गया है। नाइजीरिया, अल्जीरिया और सूडान में हुए आतंकी हमलों में बोको हराम और अल-शबाब नामक संगठनों के तार भी इसी संगठन से जुड़े हुए पाए गए हैं।

कहां है तब्लीगी जमात का मुख्यालय?

देश के बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि इस विश्वव्यापी संगठन का मुख्यालय दिल्ली की बस्ती निजामुद्दीन की बंगलेवाली मस्जिद में है और इसके प्रमुख मौलाना साद नई दिल्ली के शहजादा बाग में एक भव्य इमारत में रहते हैं। कोरोना महामारी के सिलसिले में इस संगठन के मुख्यालय को पुलिस ने सील कर दिया था। मगर अब दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर इसे पुनः संगठन के हवाले कर दिया गया है।

इस संगठन की स्थापना की कहानी भी बेहद सनसनीखेज है। 1920 में आर्य समाज ने इस्लाम में परिवर्तित हुए मुसलमानों को वापस लाने के लिए शुद्धि अभियान चलाया था, जिसकी शुरुआत दिल्ली के समीप मेवात क्षेत्र से हुई थी। इस क्षेत्र में रहने वाले मुसलमान मेव कहलाते हैं जिन्हें दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने जबरन मुसलमान बनवाया था। खास बात यह है कि 1000 वर्ष गुजर जाने के बावजूद इन राजपूत मुसलमानों का हिंदू संस्कृति से नाता जुड़ा रहा। रियासत अलवर के दीवान मेजर पॉवलेट ने रियासत के गजट में लिखा है, 'हालांकि सभी मेव मुसलमान हैं। मगर वे सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। उनमें से अधिकतर के नाम कृष्ण सिंह, बिशन सिंह, राम सिंह, शिव प्रताप सिंह और उनकी महिलाओं के नाम भी राज कंवर, राम कंवर, श्याम कंवर आदि हैं। ये हिन्दू त्योहारों को मनाते हैं और मंदिरों में भी जाते हैं। इनमें से अधिकांश कलमा और कुरान तक नहीं जानते। ये लोग हिंदुओं की भांति अपने गोत्र में शादी नहीं करते और न ही मुसलमानों की भांति मामा, चाचा, फूफा आदि के बेटे बेटियों से ही निकाह करते हैं। इनमें से अधिकांश मुसलमान होने क बावजूद गोमांस नहीं खाते हैं।'

शुद्धि आंदोलन के सूत्रधार स्वामी श्रद्धानंद थे, जिनके प्रयासों से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में हजारों की संख्या में मलकाना राजपूतों ने पुनः हिंदू धर्म स्वीकार किया। जब मेवात में शुद्धि का आंदोलन शुरू हुआ तो वह कट्टरवादी मुसलमानों को नहीं भाया। एक

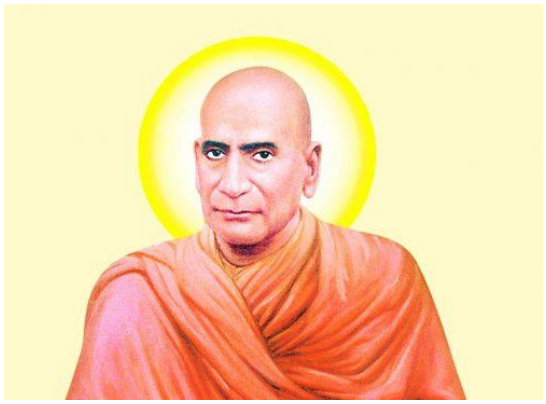

धर्मांध मुसलमान अब्दुल रशीद ने 1926 में दिल्ली के नया बाजार स्थित स्वामी श्रद्धानंद के आश्रम में घुसकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। बताया जाता है कि इस हत्यारे का संबंध तब्लीगी जमात से था। 'दक्षिण एशिया में मुस्लिम कट्टरवाद' के लेखक मुमताज अहमद न यह मत व्यक्त किया है कि इस्लामिक आतंकवाद को भड़काने में तब्लीगी जमात का प्रमुख हाथ रहा है। साहिल मायाराम ने अपनी पुस्तक 'रेजिस्टिंग रेजिम' में यह मत व्यक्त किया है कि तब्लीगी जमात की आतंकवादी पृष्ठभूमि सैयद अहमद बरेलवी के वहाबी आंदोलन और शरीयत उल्लाह के फिराजी आंदोलन से जुड़ी हुई है।

तब्लीगी जमात के संस्थापक

तब्लीगी जमात की स्थापना उत्तर प्रदेश के कांधला नगर निवासी मौलाना इल्यास ने 1926 में की थी और इसका मुख्यालय निजामुद्दीन में स्थित मस्जिद बंगलेवाली को बनाया था। मौलाना इल्यास का संबंध सुन्नी मुसलमानों के देवबंदी संप्रदाय से था। देवबंदियों के संबंध वहाबी और सलाफी विचारधारा से रहे हैं। इल्यास ने दारूल उलूम देवबंद से इस्लामिक शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद वे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित इस्लामिक शिक्षा संस्थान मजाहिर उलूम नामक मदरसा के प्रमुख भी रहे। उन्होंने मुसलमानों को एक नया नारा दिया, 'मुसलमानों मुसलमान बनो।' इसके बाद उन्होंने अपना सारा प्रयास शुद्धि आंदोलन को रोकने और जिहादी और वहाबी विचारधारा को प्रोत्साहन देने में लगा दिया। देश में जिहादी इस्लामिक विचारधारा के प्रवर्तक मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम सरहिंदी थे। मौलाना इल्यास के पीर रशीद अहमद गंगोही थे, जिनका संबंध दारूल उलूम देवबंद से था। 1946 में जब पाकिस्तान की स्थापना के आंदोलन ने जोर पकड़ा तो तब्लीगी जमात का एक केंद्र लाहौर के समीप रायविंड में स्थापित किया गया। 1949 में ढाका में भी इसका एक केंद्र स्थापित हुआ। इसके बाद इस संगठन का पैर दुनिया भर में फैल गया। इंग्लैंड में इसका मुख्यालय ड्यूस्बरी में 1978 में स्थापित किया गया जो कि यूरोप में तब्लीगी जमात की गतिविधियों का संचालन करता है। यूरोप और अमेरिका में इस समय 12 हजार से अधिक तब्लीगी जमात की मस्जिदें हैं। सोवियत यूनियन के विघटन के बाद इस संगठन ने सोवियत यूनियन के मुस्लिम बहुल देशों में पैर फैलाने का प्रयास किया। मगर किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। मोहम्मद इल्यास के निधन क बाद इस संगठन की बागडोर उनके पुत्र मौलाना मोहम्मद युसूफ ने संभाली। उनके निधन के बाद उनके बेटे मौलाना इनामुल हक इस संगठन के अमीर बने। उनक निधन होने के बाद जमात के प्रमुख मौलाना जहोरूल हसन बने। उनके मरने के बाद जमात के प्रमुख को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और आजकल इसके प्रमुख मौलाना साद हैं।

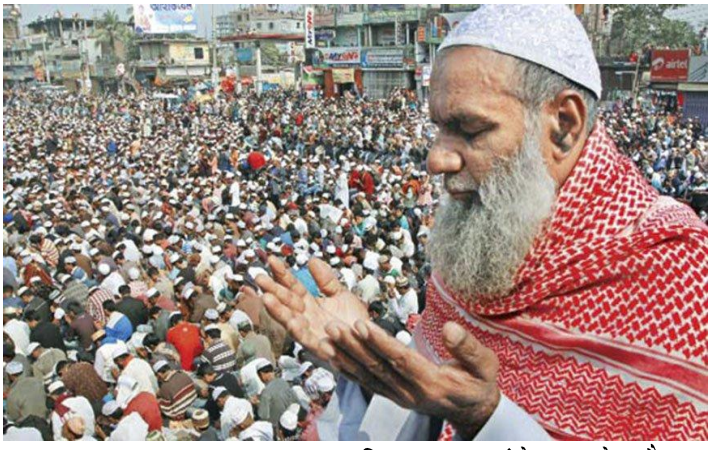

तब्लीगी जमात के प्रचार का तरीका बड़ा सीधा-साधा है। इस जमात से जुड़े हुए लोगों को हर वर्ष 40 दिन संगठन को इस्लाम के प्रचार-प्रसार के लिए देने होते हैं। ये लोग विभिन्न मस्जिदों में रात को डेरे डालते हैं और दिन भर घर-घर जाकर इस्लाम का प्रचार करते हैं। इसके अतिरिक्त इस्लाम के प्रचार के लिए इस संगठन द्वारा विश्व भर में विशाल इज्तिमाओं (सम्मेलनों) का भी आयोजन किया जाता है जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। 2016 में ढाका में ऐसा ही एक इज्तिमा हुआ था, जिसमें 40 लाख लोगों के भाग लेने का दावा किया गया था। ऐसा ही एक इज्तिमा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी हुआ, जिसमें 15 लाख लोगों के भाग लेने का दावा किया गया।

तब्लीगी जमात से जुड़े हुए प्रमुख लोग

इस विवादित जमात से जुड़े हुए लोगों में इस देश के अनेक प्रमुख लोग शामिल थे, जिनका संबंध कांग्रेस और अन्य दलों से रहा। इनमें देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन, अल्लामा इकबाल, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, खिलाफत आंदोलन के मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ. मुख्तार अहमद अंसारी, इत्तेहादुल मुस्लिमीन के संस्थापक नवाब बहादुर यार जंग, जमात-ए-इस्लामी के प्रवर्तक मौलाना अबुल हसन मादूदी, जमीयत उलेमा के संस्थापक मौलाना मोहम्मद हुसैन मदनी, जम्मू-कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला, मीरवाइज युसूफ शाह, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मौलाना इस्माइल, विख्यात मुस्लिम चिंतक और पद्म विभूषण से सम्मानित मौलाना वहीदुद्दीन खान, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय जिया उल हक आदि अनेक प्रमुख लोगों के नाम शामिल हैं।

इजरायली फौज को ईरान पर हमले की तैयारी का आदेश

इत्तेमाद (13 दिसंबर) के अनुसार इजरायल के रक्षा मंत्री ने इजरायल की फौज को ईरान पर हमले की तैयारी करने का आदेश दिया है। इन दिनों इजरायली रक्षा मंत्री अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिका इजरायल की मदद से ईरान के खिलाफ दबाव बना रहा है। उन्होंने अमेरिका को संभावित हमले के बारे में भी जानकारी दे दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया यह जान गई है कि ईरान परमाणु उर्जा के मामले पर विश्व को गुमराह कर रहा है। इसलिए यह जरूरी है कि ईरान को परमाणु अस्त्र-शस्त्र बनाने से हर कीमत पर रोका जाए। इजरायल की धमकी का उल्लेख

करते हुए ईरान के एक प्रवक्ता ने कहा कि अगर अमेरिका और इजरायल ने हम पर हमला करने की गलती की तो इनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। हम हमले का जवाब देना भलीभांति जानते हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (29 नवंबर) के अनुसार ईरानी सांसद फेरेदून अब्बासी ने कहा है कि इजरायल द्वारा ईरान के जिस परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या करवाई गई थी वे ईरान के लिए परमाणु अस्त्र-शस्त्र तैयार करने का तंत्र तैयार कर चुके थे। हम अपने देश की रक्षा करना जानते हैं। इसके साथ-साथ हम अपने दुश्मनों को भी नाकों चने चबवा सकते हैं। गौरतलब है कि ईरान सरकार से जुड़े हुए जिहादी संगठन सीरिया, वेनेजुएला, यमन, लेबनान, इराक और फिलिस्तीन में सक्रिय हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (9 दिसंबर) के अनुसार गाजा की सीमा पर इजरायल ने आयरन डोम की रक्षा व्यवस्था स्थापित कर ली है। इसके द्वारा हमास के जिहादियों को इजरायल में घुसपैठ करने से रोका जाएगा। इसके साथ ही सीमा पर बाड लगाई गई है। रडार सिस्टम तथा कमांड और कंट्रोल सिस्टम को भी बेहतर बनाया गया है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा कि इस नई व्यवस्था से इजरायल की सुरक्षा बढ़ी है और इस तंत्र के निर्माण में सवा दो लाख टन कंकरीट, डेढ़ लाख टन लोहा और इस्पात का इस्तेमाल किया गया है। यह लौह आवरण 65 किलोमीटर तक फैला हुआ है। गौरतलब है कि इजरायल ने 2016 में इस व्यवस्था को स्थापित करने की घोषणा की थी।

मुंबई उर्दू न्यूज (8 दिसंबर) के अनुसार इजरायल ने गत 18 महीनों में ईरानी परमाणु ठिकानों पर तीन बड़े हमले किए हैं। इन हमलों का संचालन इजरायल के गुप्तचर संगठन मोसाद के 1000 कार्यकर्ताओं ने किया था। इन हमलों में ड्रोन, क्वाड कॉपर और गुप्त विमानों का इस्तेमाल किया गया। इजरायली सूत्रों के अनुसार इजरायल अब इस स्थिति में है कि वह रिमोर्ट कंट्रोल द्वारा इजरायली गुप्तचर परमाणु ठिकानों को तबाह कर सके। लंदन के एक समाचारपत्र ज्यूज क्रॉनिकल ने इस बात की पुष्टि की है कि पिछले वर्ष ईरान के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह को मौत क घाट उतारा था।

मुंबई उर्दू न्यूज (6 दिसंबर) के अनुसार ईरान की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए सऊदी अरब और फ्रांस ने हाल ही में एक गुप्त समझौता किया है। यह समझौता हाल ही में जद्दा में फ्रांसीसी राष्ट्रपति और सऊदी युवराज शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के प्रयास से हुआ है।

संयुक्त अरब अमीरात का फ्रांस से राफेल विमान खरीदने का समझौता

सियासत (5 दिसंबर) के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात ने फ्रांस से 14 अरब यूरो के मूल्य के 80 राफेल युद्ध विमान खरीदने का फैसला किया है। इस समझौते की घोषणा फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के दौरे के दौरान की गई है। संयुक्त अरब अमीरात फ्रांस से भारी मात्रा में अन्य रक्षा उपकरण भी खरीद रहा है। इनमें 12 काराकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर भी शामिल है, जिनका मूल्य 17 अरब यूरो है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने अबू धाबी के युवराज और शस्त्र सेना के कमांडर शेख मोहम्मद जायेद अल नाहयान से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच अनेक रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं।

सैफ–अल इस्लाम गद्दाफी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति

मुंबई उर्दू न्यूज (4 दिसंबर) के अनुसार लीबिया की एक अदालत ने निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सफ-अल इस्लाम गद्दाफी को चुनाव में भाग लेने की अनुमति दे दी है। गद्दाफी ने इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि उन्होंने हक की बात के लिए स्वयं को खतरे में डाला है। गद्दाफी के वकील खालिद अल-जदी ने दावा किया है कि लीबिया की सरकार ने गद्दाफी परिवार के विभिन्न सदस्यों की गतिविधियों पर जो प्रतिबंध लगा दिए थे उसे भी अदालत ने हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यह हक की जीत है। अदालत के इस फैसले के बाद लीबिया के विभिन्न क्षेत्रों में सैफ-अल इस्लाम गद्दाफी के पक्ष में प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हो गया है। लोग सैफ-अल इस्लाम गद्दाफी की तस्वीरों को लेकर उनके पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में लीबिया के चुनाव आयोग ने लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के बेटे के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसके खिलाफ गद्दाफी ने अदालत में अपील की थी।

तुर्की द्वारा इजरायल से संबंध स्थापित करने की तैयारी

रोजनामा सहारा (30 नवंबर) के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने यह संकेत दिया है कि उनका देश शीघ्र इजरायल के साथ संबंध स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास यह है कि जिस तरह से संयुक्त अरब अमीरात ने मिस्र और इजरायल के साथ संबंधों को सुधारा है उसी तरह हम भी इन देशों के साथ संबंधों को सुधारें। उन्होंने कहा कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में उनके दौरे के कारण तुर्की में विदेशी पूंजी निवेश में भारी वृद्धि हुई है और अरबों डॉलर की पूंजी निवेश के संबंध में अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एर्दोगान तुर्कमेनिस्तान से वापसी पर विमान मं पत्रकारों से वाता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात ने तुर्की में दस अरब डॉलर पूंजी निवेश की योजना बनाई है। इन संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के लिए वे अगले वर्ष फिर संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करेंगे। तुर्की इस बात का प्रयास कर रहा है कि अरब देशों के साथ उसके संबंधों में सुधार आए। गौरतलब है कि हाल ही में तुर्की में जासूसी के आरोप में एक इजरायली दंपत्ति के गिरफ्तार किए जाने के बाद इजरायल में जो तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी उसके कारण उन्होंने पहली बार इजरायल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद इस इजरायली दंपत्ति को जेल से रिहा करके वापस इजरायल भेज दिया गया था।

इत्तेमाद (1 दिसंबर) के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति ने तुर्कमेनिस्तान में आर्थिक सहयोग के अधिवेशन में भाषण देते हुए इस बात पर जोर दिया कि सभी देशों को मिलकर आतंकवाद की समाप्ति के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने अपने देश में पीकेके, वाइपीजी और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जो सख्त कदम उठाए हैं उसके कारण राजनीतिक स्थिरता बढ़ी है और आर्थिक विकास का मार्ग खुला है। उन्होंने कहा कि तुर्कमेनिस्तान और तुर्की के बीच व्यापार में वृद्धि की बहुत संभावनाएं हैं। आशा है कि यह सौ अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा।

मलेशिया में विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे भवन का निर्माण

सियासत (6 दिसंबर) के अनुसार मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 118 मंजिला इमारत का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी उंचाई 2227 फीट होगी। यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत होगी। दुबई की बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे उंची इमारत है, जिसकी उंचाई 2717 फीट है। उन्होंने कहा कि मलेशिया का भवन 31 लाख स्क्वायर फीट क्षेत्र पर फैला हुआ होगा। इनमें से आधे क्षेत्र में कार्यालय होंगे। जबकि इस टावर में एक शॉपिंग मॉल, एक मस्जिद, एक होटल और दक्षिणी एशिया का सबसे उंचा ऑबर्जेवेशन डेक होगा। इस भवन का निर्माण आस्ट्रेलिया के एक वास्तु निर्माता कर रहे हैं। यह भवन त्रिकोणिय होगा। इस भवन के निर्माण की घोषणा 2010 में की गई थी। जबकि इसकी नींव 2015 में रखी गई थी। 2020 में कोविड की महामारी के कारण इसका निर्माण कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। यह भवन अगले वर्ष तक तैयार हो जाने की संभावना है।

पैगम्बर इस्लाम का चित्र बनाने वाले के खिलाफ मुकदमा

सालार (7 दिसंबर) के अनुसार दिल्ली के एक प्रकाशक के खिलाफ पैगम्बर-ए-इस्लाम का रेखा चित्र प्रकाशित करने के आरोप में श्रीनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। यह रेखा चित्र इस प्रकाशक द्वारा प्रकाशित इतिहास की पुस्तक में प्रकाशित किया गया है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने रियासत के सभी स्कूलों को यह निर्देश दिया है कि वे इस पुस्तक को अपने स्कूलों में इस्तेमाल न करें। दूसरी ओर प्रकाशक ने क्षमा याचना करते हुए कहा है कि यह गलती अनजाने में हुई है और वे इस विवादित पुस्तक को वापस ले रहे हैं।

सालार ने एक अन्य समाचार में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महामंत्री

मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का एक बयान प्रकाशित किया है जिसमें पैगम्बर-ए-इस्लाम का रेखाचित्र प्रकाशित करने की निंदा की गई है और यह मांग की गई है कि इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाकर इसके पकाशक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

बिहार की शिक्षा नीति की आलेचना

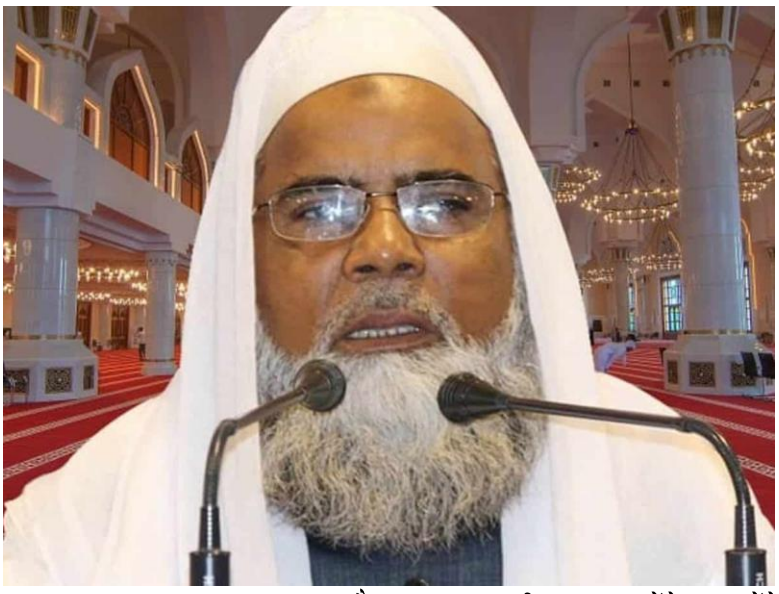

मुंबई उर्दू न्यूज (29 नवंबर) के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महामंत्री मौलाना सैफुल्लाह रहमानी ने दरभंगा में एक गोष्ठी को संबोधित करते हुए यह आरोप लगाया है कि बिहार सरकार द्वारा जो नई शिक्षा नीति शुरू की गई है उसमें जानबूझकर देश के इतिहास में मुसलमान और इस्लामिक शासकों से संबंधित सामग्री को निकाल दिया गया है। यह जानबूझकर किया गया है ताकि हमारी नई पीढ़ी मुस्लिम शासकों की भूमिका की जानकारी प्राप्त न कर सके। जबकि नई शिक्षा नीति में भजन और गीता तक का उल्लेख किया गया है। इसमें वंदे मातरम् को भी पढ़ना अनिवार्य किया गया है जो कि इस्लाम के सरासर खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जिस स्कूल में वंदे मातरम् का पाठ होगा मुसलमान उसका बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि हम हर कीमत पर अपनी अलग पहचान और इस्लाम की रक्षा करेंगे। उन्होंने मुसलमानों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में न पढ़ाएं क्योंकि सरकार जानबूझकर मुस्लिम छात्रों को इस्लाम से दूर करने का प्रयास कर रही है। मुसलमान बच्चों को मदरसों में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि वे इस्लाम और अपने पूर्वजों की भूमिका के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकें।

महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

मुंबई उर्दू न्यूज (11 दिसंबर) के अनुसार मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के अतिरिक्त महानिदेशक और एटीएस के पूर्व प्रमुख देवेन भारती और एसीपी दीपक फटंगारे सहित तीन लोगों के खिलाफ एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। इस महिला पर यह आरोप है कि उसने भारतीय नागरिकता को सिद्ध करने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। रेश्मा खान नामक इस महिला के बारे में पुलिस का आरोप है कि वह बांग्लादेशी नागरिक है और बीजेपी के उपाध्यक्ष हैदर आजम की पत्नी है। इस संदर्भ में मुंबई

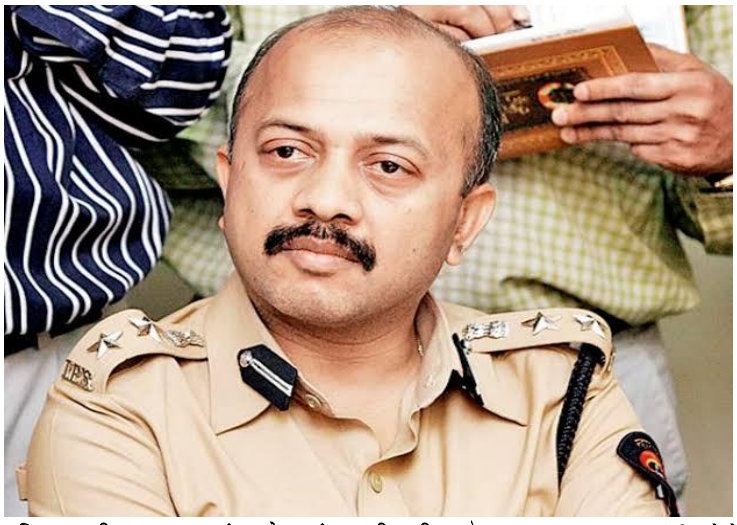

पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जांच की थी और इस रिपोर्ट के आधार पर मालवनी थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है। अभी तक इस संदर्भ में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। बताया जाता है कि इस महिला ने जब पासपोर्ट के लिए आवेदन दिया था तो उसने फर्जी दस्तावेज जमा कराए थे। बाद में जब जांच की गई तो जांच अधिकारी ने यह बयान दिया कि इस महिला के खिलाफ तत्कालीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी देवेन भारती के निर्देश पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। गौरतलब है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर यह आरोप लगाया था कि उनके हस्तक्षेप के कारण एक बांग्लादेशी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।

40 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार

मुंबई उर्दू न्यूज (1 दिसंबर) के अनुसार भिवंडी पुलिस ने नगर में विभिन्न स्थानों पर छापे मारकर 40 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है जो कि फर्जी दस्तावेज बनाकर भारत में रह रहे थे। पुलिस उपायुक्त योगेश चव्हान ने पत्रकारों को बताया कि भिवंडी पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों का पता लगाने के लिए जिले में अभियान छेड़ा है। अब तक नर्पोली थाना, कुलगांव थाना और शांतिनगर थाने की पुलिस ने अपने क्षेत्रों में सघन छापेमारी के दौरान 40 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ विभिन्न आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि ये बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में दाखिल

हुए थे और फर्जी दस्तावेज बनाकर विभिन्न फर्मों में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इन बांग्लादेशियों को नौकर रखा था उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

RNI No. DELHIN/2017/72722

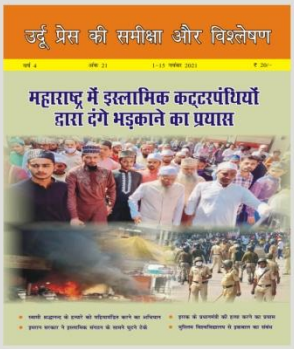

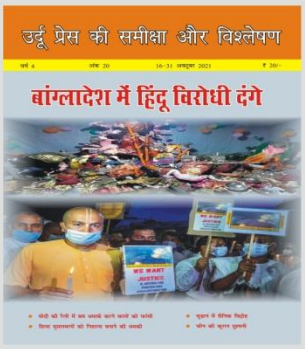

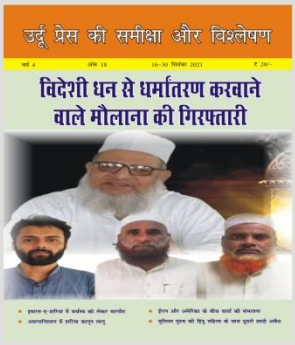

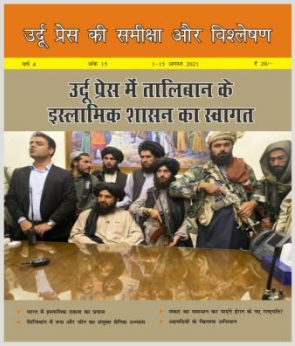

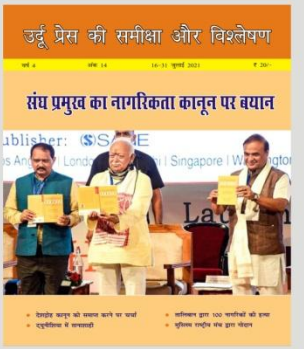

ipf INDIA POLICY FOUNDATION
॥ प्रदीप्तेम जगत् सर्वम् ॥
भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in